

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3043
(दिनांक 19.03.2025 को उत्तर देने के लिए)

मध्य प्रदेश में सामुदायिक रेडियो स्टेशन

3043. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार प्रसारण के क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेषकर मध्य प्रदेश में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को कार्यान्वित कर रही हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने खजुराहो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कट्टनी, पञ्जा जिलों और खजुराहो शहर में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किए हैं;
- (ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन स्टेशनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरुगन)

(क) से (घ): सरकार द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) स्थापित करने की नीति दिसंबर, 2002 में आरंभ की गई। तब से, दिशा-निर्देशों को समय-समय पर अद्यतन किया जाता रहा है, और इनका नवीनतम संस्करण 13.02.2024 को जारी किया गया जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात <https://mib.gov.in> पर उपलब्ध है। नीति के तहत सामुदायिक रेडियो स्टेशन विभिन्न गैर-लाभ अर्जक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। भारत सरकार सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने और उनकी मरम्मत-रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

वर्तमान में, मध्य प्रदेश में 47 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों सहित देश भर में 528 सामुदायिक रेडियो स्टेशन कार्यरत हैं। तथापि, कट्टनी, पञ्जा जिलों या खजुराहो शहर में कोई सामुदायिक रेडियो स्टेशन नहीं है।

सरकार सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन करके सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के बारे में जागरूकता बढ़ा रही है।
